संख्या-73/2026/।-1436713 /डी-257/38-2-2026/
002-38-2002(002)/3/2024

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र.
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44/लेखा-पेंशन/डी०आर०डी०ए० (ग्रेच्युटी) /2026-27, दिनांक 24 जुलाई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रु० 1100.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रू0 825.00 लाख (रूपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च 2026 में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 275.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा तथा आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वितीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन/दिशा निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501068000300 जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-2-70-X-2026-27, दिनांक 12-08-2026 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6- वित (आय-व्ययक) अनु०-2/वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु०-3
7- ग्राम्य विकास अनु०-5/8
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।